जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 | वर्षः 16 | संख्याः 251 | प्रभात | चूरू, मंगलवार 7 जनवरी, 2025 | पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 | पृष्ठ 6 | मूल्य 2.50 रु.

एलन मस्क अब केवल अमेरिका के आंतरिक मामलों के ''विशेषज्ञ'' ही नहीं रहे

वे अब अन्य देशों, उदाहरण के लिये इंगलैण्ड व जर्मनी, के राष्ट्राध्यक्षों की भी ''क्लास'' लेने लगे हैं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद एलन मस्क अमेरिका में न केवल ''एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूश्नल पावर,'' परा संवैधानिक शक्ति केन्द्र के रुप में उभर रहे हैं, बल्कि एक कूटनीतिक ''क्रशिंग बॉल'' भी बन रहे हैं। (क्रशिंग बॉल वह उपकरण है जो इमारतों को तोड़ने के काम आता है)।

हाल ही में इन्होंने ब्रिटिश सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री और ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की, जो एक तरह से ब्रिटेन और अमेरिका की एतिहासिक दोस्ती पर भारी प्रहार था।

इससे पहले एलन मस्क ने जर्मनी की सरकार और चांसलर ओलाफ शोल्ज़ की आलोचना की थी, क्योंकि वे अपराधियों पर कार्यवाही करने में असफल रहे हैं। मस्क ने जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी ए.एफ.डी. को शोलत्ज़ सरकार का बेहतर विकल्प बताया था। जर्मनी में जल्दी ही नए चुनाव होने वाले हैं और नई सरकार बनने की संभावना है।

- मजे की बात है, ट्रम्प के अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद, इन सार्वभौम देशों के प्र.मंत्री/चाँसलर आदि भी ट्रम्प को ''खुश'' रखने की दृष्टि से मस्क की इन तीखी टिप्पणियों को अपने देश के आंतरिक मामलों में दखलदांजी नहीं मान रहे, बल्कि, मस्क की टिप्पणियों का झूठा-सच्चा, विनय पूर्वक जवाब देने में लगे हैं।
- मस्क ने ब्रिटेन के वर्तमान प्र.मंत्री पर आरोप लगाया कि वर्षों ही नहीं, दशकों तक इंगलैण्ड में बच्चियों का बलात्कार व शोषण हो रहा था, कुछ पाकिस्तानी गिरोहों द्वारा, पर, ब्रिटेन की सरकार चुपचाप देखती रही, इन कृत्यों को ज्यादा प्रचारित करने व सख्त दण्डनीय कार्यवाही करने से कतराती रही, क्योंकि उसे डर था कि सख्ती करने से उन पर ''रेसिस्ट'' का ठप्पा लग सकता है, और वह अपने पर ''इस्लामी फोबिया'' होने की तोहमत भी नहीं लगवाना चाहती थी।

मस्क ने ब्रिटिश सरकार के आचरण व संस्थागत विफलताओं की इतनी कड़ी आलोचना की, कि प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर को अपने बचाव के लिए आगे आना पड़ा, पर मस्क का खुलासा इतना जबर्दस्त है कि इसका गंभीर परिणाम होगा।

मस्क ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ''घटिया'' करार दिया और कहा कि जिसने भी बच्चों के यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों की नए सिरे से जांच की मांग की, उसे स्टारमर ने कट्टर दक्षिणपंथी करार दिया।

मस्क ने मौजूदा प्रधानमंत्री की ब्रिटिश सरकार के डायरैक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन की भूमिका की भी कड़ी आलोचना की तथा उनके करीबी लोगों पर भी निशाना साधा।

मस्क का आरोप था कि सरकार और ब्रिटिश अधिकारियों के पूरे एक समूह ने पाकिस्तानी ''ग्रूमिंग गैंग्स'' द्वारा छोटी लड़कियों के यौन शोषण व दुष्कर्म के खिलाफ पीड़िताओं व उनके माता-पिता की अपीलों की अनदेखी की, क्योंकि उन्हें डर था कि उन पर रंगभेद व इस्लाम से डरने वाले का ठप्पा लग सकता है।

मस्क ने ऐसे समय में ब्रिटिश सरकार पर निशाना साधा है, जब समूची ब्रिटिश सरकार अमेरिका के नए राष्ट्रपति से अच्छे रिश्ते बनाने में जुटी है। ट्रम्प ने हाल ही में यूरोप के कई देशों की सरकारों व नेताओं की आलोचना की है, क्योंकि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डूंगरपुर में 2 माह के बच्चे में चीनी वायरस मिला

डूंगरपुर, 6 जनवरी (निसं)। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी की डूंगरपुर में दो महीने के बच्चे में पुष्टि हुई है। बच्चा 12 दिन से अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती है। बच्चा अभी स्वस्थ बताया जा रहा है। बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। परिवार के लोग बच्चे को गुजरात के मोडासा लेकर गए, जहां बच्चे को

- अहमदाबाद के अस्पताल में 12 दिन से भर्ती बच्चा अब स्वस्थ बताया जा रहा है।
- अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार, शुरु में 5 दिन बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसके बाद की जाँचों में वायरस से संक्रमित होने की बात सामने आयी थी।

आराम नहीं मिलने पर, उसे अहमदाबाद के ऑरेंज हॉस्पिटल लेकर पहुंचे।

हॉस्पिटल के डॉ. नीरव पटेल ने बताया कि शुरुआत में उसे पांच दिनों तक वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। इसके बाद हुई कई जांचों में बच्चे के वायरस से संक्रमित होने की बात सामने आई। प्रीमैच्योर डिलीवरी की वजह से बच्चे के फेफड़ों में इंजेक्शन भी लगाया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कांग्रेस दिल्ली में जीती तो महिलाओं को हर माह 2500 रूपए देगी'

कांग्रेस ने दिल्ली में ''प्यारी दीदी'' योजना की घोषणा करते हुए वादा किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जनवरी। कांग्रेस ने आज ''प्यारी दीदी योजना'' की घोषणा की, जिसके तहत, पार्टी ने वचन दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता में आने पर प्रत्येक महिला को 2,500 रूपए प्रति माह दिये जायेंगे।

इस योजना की घोषणा पार्टी की दिल्ली इकाई के कार्यालय में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन तथा पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के साथ मिलकर की।

मीडिया को संबोधित करते हुये, शिवकुमार जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा, ''हम प्यारी दीदी योजना'' लाँच कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार आयेगी। हम मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग वाले दिन इस योजना को लागू कर देंगे।''

उन्होंने कहा कि ''प्यारी दीदी योजना'' के तहत, कर्नाटक मॉडल के अनुरुप, दिल्ली की प्रत्येक महिला को 2,500 रूपए प्रति माह दिये जायेंगे।

- कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी काज़ी निज़ामुद्दीन और पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने पार्टी कार्यालय में इस योजना की घोषणा की।
- डी.के. शिवकुमार ने इस दौरान पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनने के तीन माह बाद ही सभी गारंटियां लागू कर दी थीं और उन्हें यकीन है कि दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार बनी तो यह योजना लागू होगी।
- दिल्ली प्रभारी काज़ी निज़ामुद्दीन ने कहा कि दिल्ली के लिए यह कांग्रेस की पहली गारंटी है।
- दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि पार्टी ने कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना, सभी जगह वादे निभाएं हैं। पार्टी समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है।

शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने जिन गारंटियों का वादा किया था, राज्य में सत्ता में आने के तीन महीनों के अंदर, वे सभी गारंटियों को क्रियान्वित कर दिया गया था।

कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुये, उन्होंने कहा, ''महिलाएं पूरे राज्य में बसों में फ्री यात्रा कर रही हैं, बेरोज़गार युवाओं को 3,000 रूपए दिये जा रहे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में भाजपा की मदद के लिए संघ ने 100 स्वयंसेवक उतारे

बताया जाता है कि संघ ने महाराष्ट्र व हरियाणा में भी यही नीति अपनाई थी जिससे भाजपा हारी हुई बाजी जीत गई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जनवरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिल्ली के आसन्न विधानसभा चुनावों से पूर्व जनसम्पर्क अभियान शुरु कर दिया है ताकि उसकी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को बल मिल सके।

विस्तृत जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि आर.एस.एस. का यह सम्पर्क अभियान महाराष्ट्र और हरियाणा में किये गये उसके प्रयासों की ओर भी इंगित कर रहा है, जहाँ दोनों राज्यों में भाजपा के विरूद्ध सत्ता-विरोधी माहौल और प्रशासनिक कमियों को लेकर प्रतिकूल जमीनी स्थिति को मात देकर सत्ता हासिल कर ली थी।

हरियाणा में भाजपा ने अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिये 90 में से 48 सीटें जीती थीं तथा महाराष्ट्र में भाजपा, शिव सेना (शिंदे गुट) तथा एन.सी.पी. (अजित पवार) से मिलकर बने महायुति गठबंधन ने 288 में से 228 सीटों पर विजय प्राप्त की थी।

- जानकार सूत्रों ने बताया कि गत कुछ सप्ताह से वरिष्ठ संघ नेताओं और भाजपा नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है, जिसमें चुनाव की सैंट्रल थीम सैट की गई है।
- सूत्रों ने बताया कि संघ दिल्ली में बाँग्लादेशियों व रोहिंग्या की घुसपैठ से चिंतित है, इसलिए वह दिल्ली में भाजपा को सत्ता में लाना चाहता है।
- संघ के ये 100 स्वयंसेवक अगले कुछ सप्ताहों में समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मेल-मुलाकात करेंगे और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे।
- इसी नीति की बदौलत भाजपा ने हरियाणा व महाराष्ट्र में ''एन्टी इन्कम्बैंसी'' लहर को उलट कर हरियाणा में 90 में से 48 और महाराष्ट्र में 288 में से 228 सीटें जीती थीं।

पार्टी नेताओं ने इन दोनों राज्यों में भाजपा की जीत का श्रेय आर.एस.एस. के प्रचार-अभियान को ही दिया था, जिसने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में मदद की थी।

दिल्ली में, आर.एस.एस. के करीब 100 स्वयंसेवक अगले सप्ताहों में सोशल ग्रुपों तथा प्रोफेशनल्स के साथ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अजमेर दरगाह में आज पेश होगी मुख्यमंत्री की चादर

जयपुर, 6 जनवरी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से अजमेर ख्वाजा साहब के उर्स के मुबारक मौके पर मंगलवार को चादर पेश की जाएगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान

- भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष हमीद खान मेवाती दिन में 12 बजे प्रदेश कार्यालय से चादर लेकर रवाना होंगे।

मेवाती मजार शरीफ पर मुख्यमंत्री की ओर से दी गई चादर पेश करेंगे। हमीद खान मेवाती मंगलवार दोपहर 12 बजे जयपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय से रवाना होकर 3 बजे अजमेर पहुंचेगे। चादर पेश करने के बाद, वे बुलंद दरवाजे से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का संदेश पढ़ेंगे।

रोहिणी (दिल्ली) की आमसभा में मोदी जी का ''टैलिप्रॉम्प्टर'' फेल हुआ

''टैलिप्रॉम्प्टर'' की सेवाएं अवरूद्ध होने के कारण मोदी जी के ''स्पीच लैस'' हो जाने, पर, सोशल मीडिया में एक बाढ़ सी आ गई, व्यंग और उपहासपूर्ण टिप्पणियों की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जनवरी। रविवार को दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक रैली के दौरान ''टैलिप्रॉम्प्टर'' की गड़बड़ी ने कथित रूप से प्रधानमंत्री को चुप करा दिया। जनवरी 2022 में वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम समिट के दौरान भी उन्हें ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था।

रविवार की घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री को लक्ष्य करते हुए उपहास और तानों की झड़ी लग गई।

एक सोशल मीडिया यूज़र ने फोटो पोस्ट की और लिखा, ''नेहरू जी ने टैलिप्रॉम्प्टर की बिजली काट दी।'' ज्ञातव्य है कि भाजपा भारत की हर समस्या के लिए पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराती रही है।

इतने सालों तक भाजपा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का मज़ाक बनाने के लिए बड़ी सफलता से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती आई है।

- ऐसी ही दुर्घटना जनवरी 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को ''वर्चुअली'' संबोधित करते हुए भी हुई थी।
- पर, उस दुर्घटना पर मीडिया का ज्यादा ''फोकस'' नहीं हुआ था। पर, इस बार एक आमसभा को संबोधित करते हुए यह हादसा हुआ, तो सरकार विरोधी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मौका मिल गया। मोदी कार्यशैली, वाक्चातुर्य आदि पर तंज कसने का और इस मौके का भरपूर उपयोग हुआ।

सोशल मीडिया विश्लेषक राधिका सचान का कहना है कि इस मामले में पार्टी के सबसे बड़े नेता को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है।

एक अन्य सोशल मीडिया यूज़र ने पोस्ट किया, ''टैलिप्रॉम्प्टर उनके झूठ के आगे फेल हो गया। वो भी जनता को झूठ नहीं बताना चाहता था।''

एक और यूज़र ने अपनी पोस्ट में कहा, ''बेचारे प्रधानमंत्री, टैलिप्रॉम्प्टर ने बीच में ही काम करना बंद कर दिया। उसके बिना वो एक शब्द भी नहीं बोल सकते। लोग सोचते हैं, मोदी सबको कंट्रोल करते हैं, जबकि वो खुद टैलिप्रॉम्प्टर ऑपरेटर और भाषण लिखने वाले के कंट्रोल में हैं।''

एक और प्रतिक्रिया आई, ''इलाज में फिर कमी? जब टैलिप्रॉम्प्टर फेल होता है तो संघ परिवार के ''महानतम वक्ता'' भी फेल हो जाते हैं।''

एक व्यक्ति ने कहा, ''महानतम वक्ता टैलिप्रॉम्प्टर के बिना लड़खड़ा जाते हैं और उसे ''कवर अप'' करने के लिए कैमरा दर्शकों की तरफ घूम जाता हे। क्या यह केवल बुढ़ापा है, या फिर स्क्रिप्ट भी गायब हो गई है?''

एक और यूज़र ने कहा, ''मोदी टैलिप्रॉम्प्टर प्रोमैक्स। फेलियर परमानैंट (स्थाई) है, सफलता टैम्परेरी (क्षणिक) है। वे टैलिप्रॉम्प्टर के बिना एक शब्द भी नहीं बोल सकते।''

दूसरे ने लिखा, ''आपको पता नहीं, बोलना क्या है? टैलिप्रॉम्प्टर एरर!''

आप नेता अरविंद केजरीवाल को दोषी बताते हुए एक यूज़र ने कहा, ''टैलिप्रॉम्प्टर फेल हो गया। लगता है केजरीवाल ने तार काट दिया।''

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उच्चाधिकार समिति व किसानों की वार्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई

नयी दिल्ली, 06 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने एक महीने से अधिक समय से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल सहायता देने के मामले में पंजाब सरकार की विफलता पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई सोमवार से दस जनवरी तक के लिए

- कोर्ट ने 10 जनवरी को सुनवाई से पहले वार्ता के परिणाम बताने को कहा।

टाल दी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति के सदस्यों ने डल्लेवाल एवं अन्य किसान नेताओं से वार्ता की है।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और एन के सिंह की पीठ ने पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

द्रमुक सरकार को एक के बाद एक भावनात्मक मुद्दे थमा रहे हैं राज्यपाल आर.एन. रवि

इन मुद्दों से द्रमुक सरकार असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने में कामयाब हो रही है

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जनवरी। गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल राज्य सरकारों को हद से ज्यादा परेशान कर चुके हैं, पर अगर तमिलनाडु की बात करें तो राज्यपाल आर.एन. रवि द्रमुक और राज्य सरकार को खुद इतना मसाला दे रहे हैं कि वह आसानी से उनका सामना कर रही है। वे द्रमुक को ऐसे -ऐसे भावनात्मक मुद्दे थमा रहे हैं कि उनका इस्तेमाल कर द्रमुक ना केवल असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा रही है, बल्कि अपना केन्द्र सरकार विरोधी कथानक भी जनता के सामने पेश कर रही है। राजनैतिक पर्यवेक्षक हैरान हैं कि क्या वे ''सैल्फ गोल'' कर रहे हैं।

नवीनतम मामला सोमवार को हुआ, जब राज्यपाल ने राष्ट्रीय गीत और संविधान के कथित अनादर के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया। असल में राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय गीत से पहले ''स्टेट एंथम'' (राज्य गीत) बजाया गया तो वे शीतकालीन सत्र को संबोधित करने की परम्परा निभाए बिना ही सदन से वॉक आउट कर गए और राष्ट्र गीत तथा संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया।

- सोमवार को राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य विधानसभा में ''स्टेट एंथम'' बजाने पर विरोध जताया और राष्ट्रगीत व संविधान के अपमान का आरोप लगा कर अभिभाषण दिए बिना ही सदन से वॉकआउट कर गए।
- द्रमुक सरकार ने राज्यपाल की इस हरकत को उनके तमिलनाडू विरोध की संज्ञा दी और तमिल संस्कृति का मुद्दा उठाया।
- पर, इस विवाद में अन्ना युनिवर्सिटी में हुआ ''दुष्कर्म'' कांड उपेक्षित रह गया। जब इस मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष नारेबाजी कर रहा था तभी राज्यपाल ने राष्ट्र गीत का मुद्दा उठा कर दुष्कर्म कांड पर बहस की संभावनाएं खत्म कर दीं।
- अब राष्ट्र गीत बनाम राज्य गीत के सम्मान पर विवाद छिड़ गया है। द्रमुक कोई कसर नहीं छोड़ रही है, असली मुद्दों को दरकिनार कर रही है।

राज्य में यही परम्परा है कि विधानसभा में पहले राज्य गीत बजता है, फिर राष्ट्र गीत। ऐसा लगता है कि राज्यपाल बार-बार ऐसी ही हरकतें करने पर आमादा हैं। अभी वे राज्य गीत के कारण विधानसभा से वॉक आउट कर गए तो पहले मुख्यमंत्री के किसी बयान पर या सरकार द्वारा तैयार भाषण से कुछ भाग हटाने पर।

राज्यपाल की इस हरकत पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनकी पार्टी ने राज्यपाल की तमिलनाडु -विरोधी भावनाओं को मुद्दा बनाया और कहा कि राज्यपाल यहां भाजपा व केन्द्र सरकार के पक्षकार बनकर खड़े हैं।

राज्यपाल के पारम्परिक संबोधन के बिना ही सदन से चले जाने के बाद, राजभवन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री स्टालिन और विधानसभा स्पीकर एम. अपावू ने बार-बार कहने के बाद भी बात नहीं सुनी। राज्यपाल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारतीय संविधान का ऑन लाइन पाठ्यक्रम

नयी दिल्ली, 06 जनवरी। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने वर्ष 2024 में ही भारतीय संविधान पर ऑनलाइन हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। मंत्रालय के अनुसार, 26 नवंबर 2024 को विधिक मामलों के विभाग ने संविधान दिवस

- विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग ने नालसार युनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के साथ मिलकर हिन्दी में यह पाठ्यक्रम शुरु किया है।

और भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई। संविधान दिवस पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग ने देश की सर्वोच्च नैक रैंकिंग वाले राष्ट्रीय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)